पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) राष्ट्रीय वन नीति, 1952 तथा 1988 में यह स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय लक्ष्य यह होना चाहिये कि देश के कुल भूमि क्षेत्र के कम से कम एक-तिहाई भाग पर वन अथवा वृक्ष आवरण हो । तथापि, वास्तविक वन क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 22.8% है ।

(ख) स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1989 के अनुसार देश में वास्तविक वन (वृक्ष) आवरण 19.47 प्रतिशत क्षेत्र में था ।

(ग) और (घ) जी, हां । जिन राज्यों में न्यूनतम तथा अधिकतम वर्ग कि०मी० क्षेत्र में वन आवरण हैं वे राज्य क्रमश: हरियाणा (563 वर्ग कि०मी०,) तथा मध्य प्रदेश (13191 वर्ग कि०मी०) हैं । अपने भौगोलिक क्षेत्र के अनुपात में न्यूनतम वन आवरण वाला राज्य हरियाणा (1.3%) है जबकि अधिकतम आनुपातिक वन आवरण नागालैंड (86.8%) में है ।

(ङ) स्टेट आफ फारेस्ट रिपोर्ट, 1989 के अनुसार हरियाणा में वन आवरण की कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है ।

Mahatma Gandhi Park in Kanpur

2820. PROF. SAURIN BHATTACHARYA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to refer to answer to Unstarred Question 813 given in the Rajya Sabha dated the 2nd January, 1991 and state:

(a) whether it is a fact that Government have recently received reports from the authorities of the Park that encroachments were allowed without clearance from environment department;

(b) whether it is also a fact that the asthetic value of the park has been wiped out;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the steps Government have taken in the matter?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) to (d) The Mahatma Gandhi Park, Kanpur is a city park of Kanpur and is under the administrative control of Nagar Maha Palika, Kanpur. Accordingly the information with regard to Unstarred Question No. 813 fixed for reply in Rajya Sabha on 2nd January, 1991 was asked from the State Government of Utter Pradesh. No information has been received so far.

Teak wood under social forestry

2821. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state: what incentives are being offered to encourage teak wood plantation under the social forestry scheme?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): Under the Social Forestry Programme, farm-forestry/agro-forestry is being promoted for different tree species, including teak, by way of seedlings supply, technical advice and guidance, institutional finance, etc. No separate incentives have been offered for teakwood plantations by the Government.

Deforestation in Orissa

2822. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) the number of cases of deforestation that took place in Orissa during the last three years;

(b) the action taken thereon; and

(c) the present area of forest land in Orissa?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) During the last three years, the Central Government have accorded approval of diversion of forest lands in 39 proposals.

(b) As per stipulated conditions, compensatory afforestaton is required to be done over 5982.45 hecaters in respect of these approved projects. No compensatory afforestation has been done by the State Government in respect of these projects till 1990 rains Compensatory afforestation has been done over 2059 hecatres during 1991 rains in respect of proposals approved under the Forest (Conservation) Act, 1980 since 25.10.1980. Project-wise details of the same have not been received from the State Government.

(c) The recorded forest area in Orissa is 59,555 sq. kms.

राजस्थान में सरिस्का आरक्षित वन

2823. श्री शारदा महन्ती :

श्री सोमपाल :

क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि राजस्थान में सरिस्का आरक्षित वन लगभग 800 वर्ग कि०मी० क्षेत्र में फैला हुआ है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसमें केवल एक दर्जन के लगभग बाघ रहते हैं और हाल ही के वर्षों में बाघों की संख्या में कमी हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : जी, हां ।

(ख) जी, नहीं

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र से गुजरने वाली नई सड़कों का निर्माण

2824. **श्री बेकल "उत्साही"** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में वन क्षेत्रों से गुजरने वाली नई सड़कों के निर्माण कार्य में वन विभाग द्वारा भूमि का हस्तांतरण नहीं होने से बाधायें आ रहीं हैं ; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार वन विभाग को इस बात की अनुमति देने का विचार रखती है कि वह स्वीकृति प्राप्त सभी सड़कों के लिये अपेक्षित भूमि राज्य सरकार के स्तर पर ही मध्य प्रदेश सरकार को स्थानांतरित करें ताकि राज्य में सड़कों के निर्माण से संबंधित कार्य को गति प्रदान की जा सके ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस समस्या के समाधान के लिये कोई नीति तैयार की जा रही है यदि नहीं तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) सड़कों के निर्माण के लिये वन (सरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि को प्रयोग में लाने के संबंध में केवल दो प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लंबित हैं ।